क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
4-0 ब्लोक, आगाम नवकार कॉम्पलेकक्ष, नीयर सचिन रेल्वे स्टेशन,सचिन, सूरत-394230
मो. 9879141480

दैनिक
क्रांति समय

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

पेज: 4, मुल्य 1 रु.

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
4-0 ब्लोक, आगाम नवकार कॉम्पलेकक्ष, नीयर सचिन रेल्वे स्टेशन,सचिन, सूरत-394230
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480

E-mail: krantisamay@gmail.com

सूरत, वर्ष: 1 अंक: 148, शुक्रवार, 22 जून 2018, पेज: 4, मुल्य 1 रु.

ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात

Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

बच्चों जैसा खेल खेल रही है सरकार: अखिलेश

लखनऊ। सपा मुखिया अखिलेश यादव अपने परिवार समेत छुट्टियां मनाने लंदन चले गये हों, लेकिन उनका भाजपा पर आक्रामक रुख बरकरार है। अब गुरुवार को उन्होंने ट्वीट कर यूपी की भाजपा सरकार पर उनके द्वारा कराए विकास कार्यों को रोकने का आरोप लगाया। ट्वीट के साथ उन्होंने लखनऊ के जेपी इंटरनेशनल सेंटर की निर्माणाधीन बिल्डिंग का फोटो भी शेयर किया है। इस सेंटर का अभी काफी काम बाकी है। अखिलेश ने ट्वीट किया है कि विकास गति का दूसरा नाम होता है और गति से प्रगति होती है, पर सिर्फ़ राजनीति करने वाली भाजपा सरकार ने विकास के हर काम को किसी-न-किसी बहाने रोक दिया है। ये सरकार की बचकानी हरकत है, जैसे बच्चों का वो खेल याद करें जिसमें वो किसी को चलते-चलते अचानक रोक देते हैं, सरकार वही कर रही है। अखिलेश यादव अगले महीने चार जुलाई को विदेश से लौटेंगे।

यूपी: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में दुल्हन निकली नाबालिग, अफ्सरों में मची खलबली

अलीगढ (एजेंसी)। उत्तरप्रदेश के अलीगढ़ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में नाबालिग दुल्हन का पता चलते ही अफ्सरों में खलबली मच गई। आला अधिकारियों ने जिम्मेदारों को पड़ताल करने के निर्देश दिए हैं। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब समारोह में चार मुस्लिम व 37 हिंदू जोड़े वैवाहिक डोर में बंध गए। लेकिन एक दुल्हन का दूल्हा न आने पर विवाह नहीं हो सका। मामले में जब पूछताछ हुई तो पता चला कि दुल्हन नाबालिग है। दूल्हा भी रास्ते में है। दुल्हन के नाबालिग होने की खबर लगते ही अफ्सरों में खलबली मच गई। समाज कल्याण अधिकारी एनपी सिंह ने बताया कि शादी के आवेदनों के आधार पर संबंधित निकाय ने चयन किया है, इस दुल्हन के पंजीकरण की जांच कराई जाएगी, इसकी बड़ी बहन की शादी जरूर इस समारोह में हुई है, जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।

जालौन: लालू यादव को सजा सुनाने वाले जज शिवपाल सिंह के घर पर हुई चोरी

नई दिल्ली (एजेंसी)। चारा घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को सुनाने वाले सीबीआई के तत्कालीन विशेष जज शिवपाल सिंह के घर में बुधवार की रात चोरी हो गई। वे वर्तमान में झारखंड के गोड्डा में जज हैं। शिवपाल सिंह के उत्तर प्रदेश के जालौन स्थित पुस्तैनी घर में लाखों की चोरी हुई है। बुधवार देर रात चोरों ने 1.5 से दो लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवरात और 60 हजार रुपये नकद पर हाथ साफ कर दिया। फिलहाल पुलिस मौके पर तफ्तीश में जुटी है। शिवपाल सिंह का पुस्तैनी घर जालौन कोतवाली के शेखपुर खुर्द ग्राम में है। गांव में उनके भाई रहते हैं। बुधवार की रात जज के भाई सुरेंद्र पाल अपने घर के अन्य लोगों के साथ छत पर सो रहे थे। जब गुरुवार सुबह सुबह वो नीचे आए।

यूपी: पुल के नीचे मिला हैंड ग्रेनेड, बम निरोधक दस्ता पहुंचा

देवरिया। यूपी के देवरिया जिले में गुरुवार दोपहर सनसनी फैल गई। भागलपुल के नीचे हैंड ग्रेनेड मिलने से जहां पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मच वहीं आसपास रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। जांच के लिए पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने गोरखपुर से बम निरोधक दस्ते को भी बुला लिया है। जानकारी के मुताबिक दोपहर में चरवाहों ने पुलिस को सूचना दी कि पुल कुछ संदिग्ध सामान दिख रहा है। पुलिस पहुंची तो देखा पुल के नीचे रेत में धंसी हुई चीज तो हैंडग्रेनेड है। बताया जा रहा है कि इसमें जंग भी लग गया है। वैसे एतिहातन पुल से गुजरने वाले वाहनों को रोक दिया गया।

राजपथ पर दिखा योग का जुनून

मंत्री जयंत सिन्हा, मीनाक्षी लेखी और उपराज्यपाल बैजल सहित कई प्रमुख शख्सियतों ने किया योग किया

थायागराज स्टोडियम में योग करते दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमुल्य पटनायक।

राजधानी में चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजपथ पर योग करते उपराज्यपाल अनिल बैजल व अन्य।

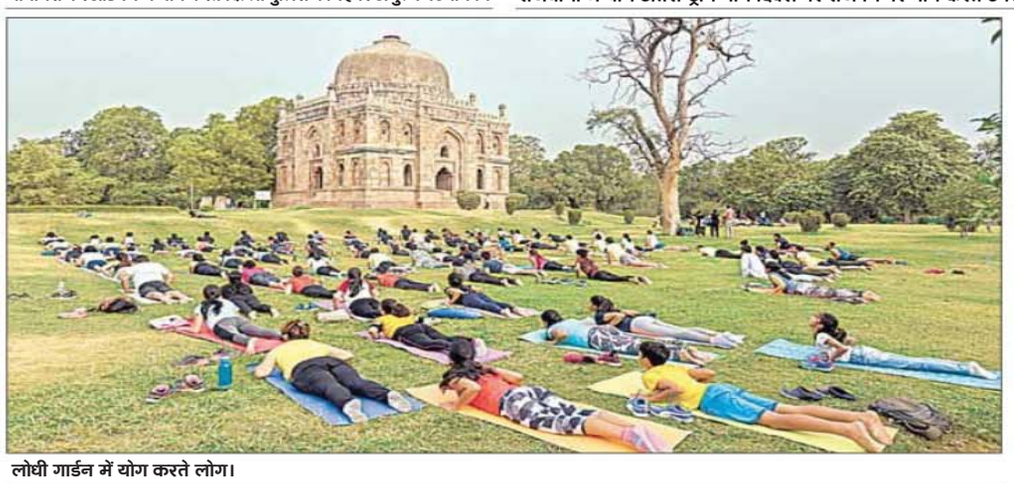

लोधी गार्डन में योग करते लोग।

लालकिले में एक ही मुद्रा में योग करती ब्रहाकुमारी।

प्रिंटिंग प्रेस की गलती से पहुंचा पेपर का गलत बंडल

इलाहाबाद (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस मेन्स 2017 परीक्षा के पेपर का गलत बंडल प्रिंटिंग प्रेस की गलती से परीक्षा केंद्र तक पहुंचा था। इस गलत बंडल को खोलने की चूक जीआईसी में हुई। वहां मौजूद आयोग के पर्यवेक्षक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट ने बिना पैकेट देखे ही पेपर बंटवा दिया।

आयोग प्रिंटिंग प्रेस के साथ ही अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। आयोग पेपर प्रकाशन की पूरी प्रक्रिया अति गोपनीय तरीके से करता है। व्यवस्था है कि प्रिंटिंग प्रेस पेपर के लिए एक बड़ा बंडल तैयार करता है। इस बंडल में 24-24 पेपर के आठ से दस पैकेट रखे जाते हैं। बंडल और पैकेट दोनों के ऊपर पेपर का नाम और पाली आदि लिखा हुआ होता है। जीआईसी में जो बंडल पहुंचा था, उसके ऊपर तो सामान्य हिन्दी प्रथम पाली लिखा हुआ था लेकिन अंदर निबंध के पेपर थे। आयोग सूत्रों के मुताबिक, इस पैकेट पर निबंध द्वितीय पाली लिखा हुआ था। लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। बंडल केंद्र व्यवस्थापक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और आयोग के पर्यवेक्षक के सामने खोला जाता है, फिर प्रश्न पत्र का पैकेट कमरों में भेजा जाता है, जो कक्ष निरीक्षक की मौजूदगी में खुलता है। बंडल खोलने के बाद किसी ने नहीं देखा कि पैकेट पर निबंध लिखा हुआ है। आयोग सूत्रों के मुताबिक अगर बंडल खोलने के बाद गलती पकड़ ली जाती तो आधे घंटे में पेपर बदला जा सकता था। सचिव जगदीश का कहना है कि पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। बहुत जल्द स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी। उधर, जीआईसी प्रबंधन का तर्क है कि पेपर पहुंचाना आयोग की जिम्मेदारी है, आयोग से जो पेपर आया था, उसे बांट दिया गया।

क्राइम ब्रांच के सामने पेश होकर दाती महाराज ने दी सफाई

झूठे मामले में फंसा मांग रहे 32 करोड़

नई दिल्ली (एजेंसी)। दाती महाराज ने बुधवार को फिर अपराध शाखा के समक्ष पेश होने के अपने पर लगे दुष्कर्म के आरोप पर सफाई दी। उनका कहना है सचिन जैन, अभिषेक अग्रवाल व नवीन गुप्ता ने मिलकर झूठे मामले में फंसाने का षडयंत्र रचा है। आरोप लगाने वाली युवती और उसके पिता को भी इसमें शामिल किया गया है।

इन सबकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच होनी चाहिए। इस दौरान कुछ देर के लिए वे भावुक भी हुए तो कभी मुस्कराकर अपना पक्ष रखते नजर आए। दाती महाराज का कहना था कि उन्हें फंसाया जा रहा है, वह दो-ढाई वर्ष से युवती के संपर्क में ही नहीं हैं। उनके आश्रम में अभिषेक अग्रवाल आया करता था, जिसने उनके नाम पर कुछ लोगों के साथ लेन-देन किया। अब नवीन गुप्ता

कहा, सचिन जैन, अभिषेक अग्रवाल व नवीन गुप्ता ने झूठे मामले में फंसाने का रचा षड्यंत्र

और सचिन जैन उनसे 32 करोड़ रपए की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभिषेक द्वारा किए गए किसी भी लेन-देन की जानकारी नहीं थी। दुष्कर्म के आरोप लगाकर उन्हें बदनाम और फंसाने की एक चाल है।

सचिन जैन, नवीन गुप्ता व पीड़िता के पिता के मोबाइल नंबर की जांच होनी चाहिए, ताकि सचाई सामने आ सके। दाती महाराज ने कहा वह मैं भगोड़ा नहीं हूं, मैं पुलिस को जांच में सहयोग करता रहूंगा। सचिन जैन ने मुझे बर्बाद करने की धमकी दी थी, मुझसे पैसे मांगे। वह इतनी बड़ी राशि कहां से लाकर देते। मैं 12-13 वर्ष से बच्चियों के लिए अस्पताल बना रहा हूं, अस्पताल देने के लिए कहा, शनिधाम की पार्किंग मांगी। अगर उन्होंने कोई गुनाह किया है तो फांसी पर चढ़ा दो। सचिन जैन मेरे पास 10 साल से था। नारी को विषय मत बनाइए। अभिषेक, नवीन और सचिन के बीच क्या लेन-देन हुआ, उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है।

दाती महाराज ने कहा कि उनके आश्रम में आने वाली बेटियों और वहां से जाने वाली बेटियों से शपथ पत्र भरवाया जाता है।

इस सबके बारे में वह पुलिस को पुरी जानकारी दे चुके हैं। नवीन और सचिन भी उनके आश्रम में रहे हैं। दाती महाराज सहित उनके भाइयों पर लगे दुष्कर्म के आरोप के मद्देनजर चाणक्युपरी स्थित कार्यालय में आज भी पूछताछ की गई।

एक पिस्टल व दो कारतूस बरामद

गोली चलाकर रंगदारी मांगने वाला धरा गया

नई दिल्ली (एजेंसी)। द्वारका जिला पुलिस ने गोली चलाकर रंगदारी मांगने वाले एक बादमाश को गिरफ्तार कर उससे एक था। पुलिस ने दावा किया कि दबोचा गया शातिर आरोपी अपना गैंग बनाकर दिल्ली का टॉप मोस्ट बदमाश बनना चाहता था। आरोपी की पहचान नकुल घुम्मनहेड़ा (23) के तौर पर की गई और आरोपी के पास से एक पिस्टल व दो कारतूस बरामद किए हैं।

फिलहाल द्वारका जिला पुलिस नकुल से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त संतोष कुमार मीणा के अनुसार 22 मई को मलिकपुर निवासी छापसिंह के घर पर नकुल व उसके साथियों ने अचानक धावा बोल दिया था। पुलिस को जांच में पता चला कि नकुल ने पीड़ित छाप सिंह को मोबाइल पर कॉल कर उससे रंगदारी मांगी थी और मना करने पर आरोपियों ने उसके घर पर हमला किया था।

आरोपियों पे पथराव करने के अलावा घर में लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए थे, लेकिन पीड़ित ने घटनाक्रम का वीडियो बना लिया था। इस बाबत मामला दर्ज किया गया और स्थानीय पुलिस के अलावा जिले की स्पेशल स्टॉफ पुलिस भी आरोपी की तलाश कर रही थी। इस बीच मंगलवार को सूचना मिली कि आरोपी अपने गांव में किसी रिश्तेदार से मिलने आने वाला है। इस सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी को उसके गांव से दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से एक पिस्टल व कारतूस जब्त कर दिए।

आरोपी ने बताया कि उसे नशे की लत है और मामूली बात को लेकर गोली चलाने से नहीं चूकता था। चार साल पहले उसने मामूली बात को लेकर बाबा हरिदास नगर इलाके में एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया था। इसके बाद आरोपी ने लोगों से रंगदारी वसूलना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में छाप सिंह से रु पए मांगे गए थे। मना करने पर उस पर हमला किया गया था।

किसी ने नहीं की मदद वीडियो वायरल

ट्रेन से कटा अपना पैर खुद ही उठाकर चढ़ा प्लेफार्म पर

भिवानी (एजेंसी)। भिवानी रेलवे स्टेशन पर मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ते समय पैर फिसलने से गिरे एक व्यक्ति का पैर कट गया। इसके बाद भी व्यक्ति ने हिम्मत नहीं हारी और कटा पैर खुद ही उठाकर पहले प्लेटफार्म पर रखा और फिर खुद फ्लेटफार्म पर चढ़ गया। इस घटना का वीडियो बनाते रहे लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। यह घटना 17 जून की है मगर अब इस घटना का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में दिख रहा है कि वहां मौजूद पुलिस वालों ने भी व्यक्ति की मदद नहीं की। पुलिस वाले प्लेटफार्म पर खड़े होकर सिर्फ उसका हाथ खींचते नजर आए। थाना जीआरपी भिवानी से मिली जानकारी के अनुसार 17 जून को जैन चौक निवासी कृष्ण कुमार पत्नी के साथ हादसे में घायल रिश्तेदार का हालचाल पूछने हिसार जा रहे थे। रेलवे स्टेशन पर पत्नी को ट्रेन में बैठाकर वह पानी लेने चले गए। इस दौरान ट्रेन चलने लगी तो वह दौड़कर गाड़ी में चढने लगे। चढ़ते समय पैर फिसलने से वह गिर गए और उनका एक पैर कट गया। इसके बाद भी वह कुछ समय मदद के लिए इंतजार करते रहे लेकिन वहां खड़े लोग मदद करने की बजाय वीडियो बनाने लगे तो उन्होंने खुद हिम्मत करके अपना कटा पैर प्लेटफार्म पर रखा और फिर खुद एक पैर के सहारे खड़े होकर प्लेटफार्म पर चढ़ गए। कृष्ण को हिसार के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज हो रहा है। जीआरपी भिवानी में तैनात एएसआई राजबीर सिंह ने यह जानकारी दी और बताया कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि लोग उसकी मदद करने की बजाय उसका विडियो बनाते रहे जो कि शर्मनाक है। उन्होंने इस बात को गलत बताया कि पुलिस ने उसकी मदद नहीं की। उन्होंने बताया कि पुलिस को जानकारी मिलने के बाद उसे तुरंत उपचार के लिए ले जाया गया।

पुलिस पूछताछ के बाद तीनों रिहा

धुत तीन युवकों ने की संसद में घुसने की कोशिश

नई दिल्ली (एजेंसी)। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए बाइक सवार तीन युवकों ने रात को संसद में घुसने का प्रयास किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक तेज रफ्तार से बाइक लाकर आरोपियों ने संसद भवन के गेट पर लगे बेरिकेड को टक्कर मारी, लेकिन वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने तीन युवकों को पकड़ लिया। बाद में उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। खुफिया ब्यूरों समेत दिल्ली पुलिस ने आरोपी युवकों से पूछताछ की और जांच कारवाई में संतुष्ट होने के बाद तीनों को छोड़ दिया।पुलिस सूत्रो के अनुसार मंगलवार देर रात तीन बजे पुलिस को कॉल मिली थी कि बाइक सवार दो-तीन युवकों ने संसद भवन परिसर में गेट संख्या तीन के रास्ते घुसने की कोशिश की है। हालांकि मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियरे ने उन्हें पकड़ लिया गया है। इस बात की जानकारी स्थानीय पुलिस को भी दी गई। जिसके बाद मामले से खुफिया ब्यूरों को भी अवगत कराया गया। संसद के संयुक्त निदेशक समेत अन्य सुरक्षा टीम और संसद मार्ग थाने की टीम ने संयुक्त रूप से इन युवकों से पूछताछ की। आरोपियों की पहचान शकूरपुर निवासी 22 वर्षीय तरुण और दो नाबालिगों के रूप में की गई। पुलिस ने बताया कि तीनों ही शराब के नशे में थे और इनके पास में शराब की बोतल भी मिली। पूछताछ के बाद उन्हें थाने की पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस के अनुसार तीनों लड़के रात को शराब पीकर बाइक से लुटियन इलाके में घूम रहे थे।

संपादकीय

शरणार्थी समस्या

कहा जाता है कि शरणार्थियों की संख्या दुनिया के असंतोष और हिंसा का सबसे बड़ा आईना होती है। इस लिहाज से देखें, तो दुनिया में यह अशांति और हिंसा लगातार बढ़ रही है। कम से कम संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के आंकड़े तो यही बताते हैं। एजेंसी हर साल शरणार्थियों की संख्या के जो आंकड़े जारी करती है, उसमें लगातार पांचवें साल बढ़ोतरी हुई है। ताजा आंकड़ों के हिसाब से इस समय दुनिया में 690 लाख लोग ऐसे हैं, जो या तो किसी दूसरे देश में शरण ले चुके हैं या शरण पाने की उम्मीद में बैठे हैं। यानी शरणार्थियों की यह संख्या कई देशों की आबादी से ज्यादा है। यह भी सच है कि शरणार्थियों के दर्द को हम सिर्फ उनकी संख्या से नहीं समझ सकते। कोई भी अपनी धरती, अपने लोगों से दूर अनजानी धरती पर नहीं बसना चाहता, लेकिन हालात उन्हें मजबूर कर देते हैं। पराए मुल्क में अपने जीवन और अपनी गृहस्थी को फिर से खड़ा करने का संघर्ष बहुत कठिन होता है। अक्सर उन्हें संघर्ष सिर्फ हालात से ही नहीं करना होता, उन दुराग्रहों से भी करना होता है, जो शरणार्थियों को शरण देने वाले देश की आबादी में होते हैं। इस तरह के दुराग्रह हमेशा से ही रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से कई जगहों पर इसे लेकर बाकायदा राजनीति होने लगी है, जिसने शरणार्थियों की समस्या को और जटिल बना दिया है।.

एक तरफ शरणार्थियों की यह संख्या परेशान करने वाली है, तो वहीं एजेंसी की रिपोर्ट के कुछ आंकड़े हैरान करने वाले भी हैं। रिपोर्ट बताती है कि पिछले साल 7,400 भारतीयों ने अमेरिका में शरण पाने के लिए अर्जी दी है। इतना ही नहीं वहां शरण का इंतजार कर रहे भारतीयों की कुल संख्या 10,000 पार कर गई है। दूसरे बहुत से देशों के मुकाबले यह संख्या बहुत कम भले ही हो, लेकिन हैरत में डालने वाली तो है ही। भारत में इस वक्त न तो किसी तरह का युद्ध चल रहा है, न किसी इलाके में इस तरह की हिंसा हो रही है कि लोगों को शरण लेने के लिए कहीं जाना पड़े। उसके बावजूद अगर यह संख्या इतनी ज्यादा है, तो हमें जांच करनी चाहिए कि ये लोग आखिर हैं कौन? संभव है कि कुछ लोग आर्थिक संभावनाओं या किन्हीं अन्य कारणों से अमेरिका में जाकर बसना चाहते हों और उन्होंने शरणार्थी वाला यह रास्ता अपना लिया हो। पिछले दिनों एक खबर आई थी कि बैंक घोटाले के आरोपी नीरव मोदी ने ब्रिटेन में शरण की मांग की है, तो क्या इस फेहरिस्त में ऐसे लोग भी हैं? ऐसा है, तो पूरी रिपोर्ट पर ही प्रश्न चिह्न लग जाएगा।.

इस बार की शरणार्थी रिपोर्ट के कुछ आंकड़े उम्मीद जगाने वाले भी हैं। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पिछले 16 साल में 52 लाख अफगान शरणार्थी अपने देश लौटे हैं। यह अफगानिस्तान में शांति (आंशिक ही सही) और उम्मीदों की वापसी का संकेत तो है ही, साथ ही हमें यह भी बताता है कि शरणार्थी का अर्थ एकतरफा यातायात ही नहीं होता। हालात अगर सामान्य हों, तो लोग अपनी धरती, अपने माहौल में लौटना चाहेंगे। अफगानिस्तान ही नहीं, ऐसा कई जगहों और कई मौकों पर हुआ है। ये उदाहरण बताते हैं कि हालात को बदलकर समस्या को पूरी तरह खत्म नहीं, तो कम अवश्य किया जा सकता है। हालांकि शरणार्थी समस्या का पूरा समाधान तभी होगा, जब पूरी दुनिया युद्ध, हिंसा, असंतोष और नफरत से मुक्त होगी।.

भारत की अपेक्षा

नेपाल के प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली चीन की छह दिवसीय यात्रा पर हैं। चीन सरकार द्वारा नियंत्रित अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस यात्रा पर तंज कसते हुए लिखा है कि भारत को ओली की यात्रा से निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि नेपाल में उसका प्रभाव कम नहीं होगा। नेपाल एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है, और नेपाल समेत किसी भी देश की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करना भारत की पारंपरिक नीति रही है। इस राह पर चलते हुए नई दिल्ली किसी देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करती। फिर, ओली की यह दूसरी चीन यात्रा है। पहली यात्रा मार्च, 2016 में हुई थी। वह जब गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। इसलिए उनकी यह यात्रा भारत के लिए निराशा की कोई वजह नहीं हो सकती। हां, इतना जरूर है कि भारत और नेपाल की सीमाएं खुली हुई हैं, इस कारण दोनों देशों की सुरक्षा व्यवस्था परस्पर जुड़ी हैं। अलबत्ता, भारत कभी नहीं चाहेगा कि नेपाल भारत विरोधी गतिविधियों का केंद्र बने। ओली चीन समर्थक माने जाते हैं। वह चीन की महत्वाकांक्षी ''वन बेल्ट, वन रोड' संपर्क परियोजना के साथ हैं। उन्होंने एक साक्षात्कार में स्वीकार किया है कि चीन के साथदो साल पहले हुए करार में बेल्ट और रोड परियोजना के ढांचे के तहत सहयोग को लेकर समझौता ज्ञापन (एमओयू) को लागू करने के लिए नेपाल प्रतिबद्ध है। नेपाली प्रधानमंत्री का रुख भारत को असहज करने वाला है क्योंकि चीन की यह परियोजना भारत की संप्रभुता और अखंडता को रौंदने वाली है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विश्व मंच से इसका विरोध करने से पीछे नहीं हटते। पिछले दिनों चीन में संपन्न शंघाईसहयोग परिषद की बैठक में भी मोदी ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया था। चूंकि नेपाल की भू-राजनीतिक स्थिति ऐसी है कि चीन चाहकर भी नेपाल की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं बना सकता। भारत पर उसकी निर्भरता बनी रहेगी। भारत-नेपाल के बीच सदियों से धार्मिक-सामाजिक-सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। दोनों देशों के सुरक्षा हित भी परस्पर जुड़े हुए हैं। लिहाजा नेपाल को चीन के साथअपने संबंधों को मजबूत करने की दिशा में भारत के सुरक्षा हितों का ध्यान रखना होगा। प्रधानमंत्री ओली से भारत इतनी ही अपेक्षा रखता है।

कटाक्ष/ सहीराम

तेरा धरना, मेरा धरना

इधर दिल्ली धरनों में बंटी हुई है। दिल्ली में बंटवारे कई तरह के हैं। अमीर-गरीब वाला तो होगा ही। वह तो शाश्वत है। एक अमीर दिल्ली है, एक गरीब दिल्ली है। एक जमना के इधर की दिल्ली है, एक जमना के उधर की। एक दिल्ली शहर है, एक दिल्ली देहात। नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली का बंटवारा तो और भी पुराना है। पुरानी दिल्ली की याद या तो परांठे खाने के लिए आती है, या फिर रमजान के दिनों में, जब पुरानी दिल्ली जीवंत हो उठती है। लजीज खानों के लिए ही पुरानी दिल्ली को याद किया जाता है। कपड़ों, जेवरों और थोक के सामान की खरीददारी के लिए भी। सत्ता के लिए नई दिल्ली है। नई दिल्ली में एक एनडीएमसी एरिया है, जो केंद्र का है, दूसरा एमसीडी जो दिल्ली का है। एक दिल्ली पूर्वांचलियों की है, एक पंजाबियों की। एक बंगालियों की है, थोड़ी-बहुत दक्षिण वालों की भी। एक दिल्ली स्लम है, एक पॉश। एक दिल्ली सुविधाओं से भरपूर है। एक समस्याओं और वंचनाओं से भरपूर। एक वंचितों की दिल्ली है। एक खाए-अघायों की। न जाने कितने बंटवारे हैं। पर इन दिनों दिल्ली धरनों में बंटी है। यह तेरा धरना है। यह मेरा है। तेरे धरने से मेरा धरना वैसे ही अच्छा है, जैसे एक जमाने में तेरी कमीज से मेरी ज्यादा कमीज सफेद होती थी। तुम एलजी के घर में धरने पर बैठ गए। किसी के घर में घुस कर बैठना कोई अच्छी बात है भला? पर लो अब हम तुम्हारे दफ्तर में बैठ गए। देखो कितना जायज, कितना उत्तम! तुम राजनीति करते हो। छीः छीः कितने घटिया, कितने क्षुद्र हो। हम राजनीति नहीं करते। पर तुम करोगे तो क्या हम नहीं करेंगे? तुम प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शन करोगे तो हम क्या तुम्हें छोड़ देंगे। हम तुम्हारे घर पर प्रदर्शन करेंगे। असल बात यह है कि तुम से कोई काम नहीं हो रहा, तो गद्दी छोड़ दो ना। वैसे तो हमने भी कौन से काम कर डाले। तुम कहते हो कि तुम दिल्ली की जनता के साथ हो। तो क्या हम दिल्ली की जनता के साथ नहीं हैं? तुम कह रहे हो कि हमने कोई वादे पूरे नहीं किए। लो हम कहते हैं कि तुमने कोई वादा पूरा नहीं किया। जनता तुम से दुखी है। अच्छा? तो क्या जनता तुमसे खुश है। जो भी हो पाले खींचे हुए हैं। इस पार हमारा धरना, उस पार तुम्हारा धरना।

तो फिर सेंसर बोर्ड की जरूरत ही क्या

विजय गोयल, संसदीय कार्य राज्यमंत्री

हाल ही में आई फिल्म वीरे दी वेडिंग ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा अश्लीलता का। फिल्म के संवाद को सुनकर यह सवाल फिर मौजूं हो गया है कि क्या वाकई देश में राष्ट्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, यानी सेंसर बोर्ड की कोई जरूरत बची है? इस फिल्म में द्विअर्थी संवादों, विशुद्ध गालियों और दृश्यों का जिस तरह बार-बार इस्तेमाल हुआ है, वह चौंकाने वाला है। जो लोग वीरे दी वेडिंग को स्वस्थ हास्य फिल्म समझकर सिनेमा हॉल पहुंचे, उन्हें बड़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। यदि सेंसर बोर्ड गालियों को बैन न करने के लिए तर्क देता है कि यह समाज में प्रचलित शब्दावली है, तो बोर्ड की जरूरत ही क्या है? उसकी जिम्मेदारी है कि फिल्म के माध्यम से समाज में प्रचलित बुराइयों को बढ़ावा न मिले और समाज में गलत संदेश न जाए। अच्छा होता कि फिल्म के शुरू में और बीच-बीच में भी 'वयस्कों के लिए' और 'अश्लील संवाद' जैसी हिदायतें दी गई होतीं। फिल्म बनाने वालों का आत्मविश्वास भी देखिए कि उन्होंने ऐसी फिल्म के लिए करोड़ों खर्च कर दिए, इस यकीन के साथ कि फिल्म पास जरूर होगी।

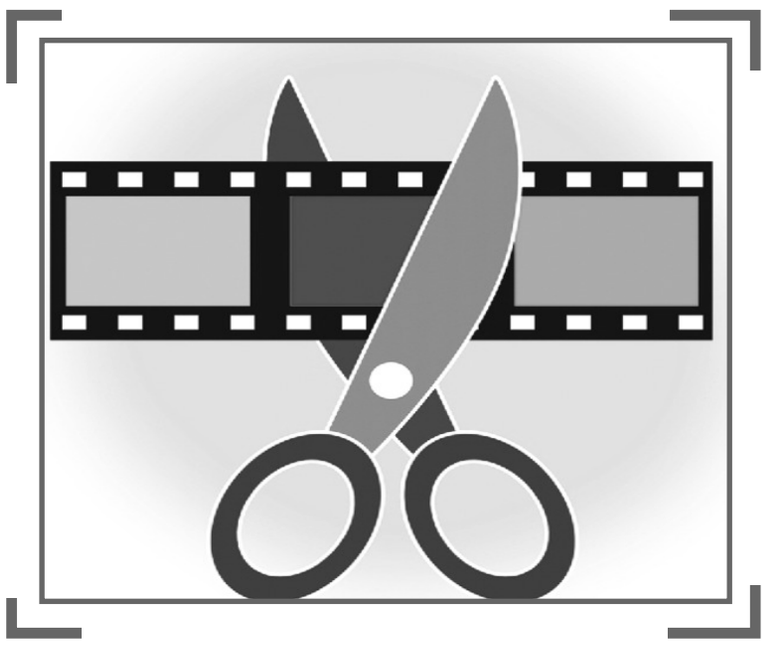

सेंसर बोर्ड की कैंची किस नियम से चलती है, यह समझ से परे है। इसकी दो मिसाल हैं। पहली, 1975 में आई फिल्म आंधी को लेकर हुआ विवाद, जिसके बारे में कहा गया था कि इसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन का गलत चित्रण किया गया है। विवाद बढ़ने पर इंदिरा गांधी के दो सहायकों ने फिल्म देखने के बाद रिलीज की इजाजत दी थी। लेकिन 20 हफ्तों के बाद फिल्म को फिर बैन कर दिया गया। सेंसर बोर्ड का कहना था कि हीरोइन के 'ड्रिंकिंग' और 'स्मोकिंग' वाले सीन को फिर से शूट किया जाए। दूसरी मिसाल, कुछ समय पहले आई एक फिल्म से 'साला' शब्द हटाने पर सेंसर बोर्ड का अड़ना। वह भी तब, जब हमारे यहां कमीने और रासकल्स के नाम से फिल्में ही मौजूद हैं, साला मैं तो साहब बन गया जैसे गाने हैं। और अब वीरे दी वेडिंग में आपको वह सब मिलेगा, जिसे इन दोनों उदाहरणों के हिसाब से बैन हो जाना चाहिए था। लेकिन इसके विरोध में कोई बोला ही नहीं। मैंने पिछले दिनों एक ऐसी फिल्म देखी, जिसमें कई सीन में किरदार सिगरेट का धुआं उड़ाते नजर आ रहे थे, लेकिन इस दौरान छोटे अक्षरों में एक चेतावनी आती थी, जिसे पढ़ना भी मुश्किल था। अश्लील दृश्यों के मामले में भी ऐसा हो सकता है, जिसमें दर्शक अपने विवेक के अनुसार आंखें मूंदने के लिए स्वतंत्र हों। कुछ लोगों का कहना है कि सेंसर बोर्ड हर फिल्म की शुरुआत में एक चेतावनी लगा दे, यह फिल्म फलां श्रेणी की है, जैसे अश्लील, डरावनी, अभद्र भाषा, हिंसक आदि और देखने का फैसला दर्शकों पर छोड़ दे। उनका तर्क है कि सिगरेट और शराब की पैकिंग पर भी ऐसी ही चेतावनी होती है, बाकी इसके उपभोग करने वाले की मर्जी। इससे सेंसर बोर्ड फिल्मों में बेतुकी काट-छांट के आरोपों से भी बरी हो जाएगा। टेलीविजन खुद अपने को सेंसर करता है। समाचार चैनलों और टीवी सीरियल अपने कंटेंट की निगरानी अमूमन खुद करते हैं। क्या यही काम फिल्मों पर छोड़ा जा सकता है? बोर्ड फिल्म को सेंसर करने की बजाय जिस दर्शक-वर्ग के लिए उसे बनाया गया है, उसके अनुसार फिल्मों की रेटिंग कर दे, बस। सेंसर बोर्ड चाहे, तो सर्वे करा डाले और फिर जो समाज चाहता है, वही परोसा जाए। एक सूची बन जाए कि बस इतने प्रकार के काम, संवाद या दृश्य सेंसर होंगे। मेरा विरोध इस बात को लेकर नहीं है कि समाज में क्या स्वीकार्य है और क्या अस्वीकार्य? मेरा सवाल यह है कि हम सेंसर बोर्ड का खर्चा क्यों उठा रहे हैं? मैं समझता हूं कि सोशल मीडिया पर कंटेंट को नियंत्रित करने की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन जहां इस पर नियंत्रण संभव है, वहां भी नहीं हो रहा है। ऐसा है, तो सेंसर बोर्ड को भंग क्यों न कर दिया जाए?

कुछ फिल्मकार भी सवाल उठाते रहे हैं कि आखिर भारत में सेंसरशिप क्यों होनी चाहिए? वे मानते हैं कि फिल्मकार खुद तय कर सकते हैं कि क्या दिखाना है और क्या नहीं? हालांकि सेंसर बोर्ड के पक्ष में खड़े होने वाले मानते हैं कि सिनेमा एक व्यावसायिक माध्यम है, जिससे निर्माताओं का फायदा भी जुड़ा है। इसे सिर्फ फिल्मकारों के विवेक पर नहीं छोड़ा जा सकता। चूंकि फिल्मों का समाज पर गहरा असर होता है, इसीलिए फिल्मकारों की जिम्मेदारी तय करने वाली संस्था की जरूरत हमेशा रहेगी। अगर फिल्मों को सिर्फ निर्माताओं के भरोसे छोड़ दिया गया, तो वे फिल्म की व्यावसायिक सफलता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए प्रदर्शन से पहले सरकार तय करे कि फिल्म कोई गलत संदेश तो प्रसारित नहीं कर रही है। अगर सेंसर बोर्ड यह सब देख ही नहीं रहा, तो उसका होना बेमानी हो जाता है। फिल्मकार खुद कंटेंट तय करें, तो कम से कम सरकार पक्षपात के आरोपों से दूर रह पाएगी।

वीरे दी वेडिंग से जो सिलसिला शुरू हुआ है, वह आगे बढ़ने वाला है और हमारे घरों की मॉडर्न भाषा और संवाद का स्तर यही होने वाला है। क्या हम इस तरह की चीजों के लिए तैयार हैं?

सेंसर बोर्ड जिस तरह से अनावश्यक आपत्तियों, रिलीज की तारीख करीब आने तक फिल्मों को लटकाने और दूसरे आरोपों-आलोचनाओं का शिकार रहा है, उसे देखते हुए हमें फिल्मों के आकलन की प्रक्रिया को नए तरीके से अंजाम देने की जरूरत है। जनवरी 2016 में सेंसर बोर्ड में सुधार के लिए श्याम बेनेगल की अध्यक्षता में गठित कमेटी की जो सिफारिशें मीडिया के हवाले से सामने आई हैं, उसके मुताबिक कमेटी ने कहा है कि सेंसर बोर्ड का रोल सिर्फ उतना हो, जितना उसे बनाए जाने का मकसद था, यानी सेंसर बोर्ड सिर्फफिल्मकारों को सर्टिफिकेट दे, न कि काट-छांट पर सलाह। फिल्म पर प्रतिबंध लगाने का हक सिर्फकेंद्र सरकार को देने की सिफारिश भी कमेटी ने की है। सिनेमेटोग्राफ ऐक्ट में बदलाव अभी विचाराधीन है, इसीलिए यह वक्त बेहद मुफीद है कि समाज में भी सेंसर बोर्ड की प्रासंगिकता और वक्त के मुताबिक उसमें बदलाव पर बहस छिड़े। यह दर्शकों के भी हित में होगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

> यह वक्त बेहद मुफीद है कि समाज में सेंसर बोर्ड की प्रासंगिकता और वक्त के मुताबिक उसमें बदलाव पर बहस छिड़े। यह दर्शकों भी हित में होगा।

ग्राम न्यायालय योजना

सेहत की सजग पारी की जरूरत

अभिषेक कुमार सिंह

इंग्लैंड दौरे पर जाने वाली भारतीय क्रिकेट टीम से मध्यक्रम के बल्लेबाज अंबाती रायडु बाहर हो चुके हैं। इसकी वजह उनकी परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि वह यो-यो टेस्ट है, जिसमें वह पिछले दिनों नाकाम रहे। उल्लेखनीय है कि कप्तान विराट कोहली समेत इस टेस्ट में टीम के बाकी खिलाड़ियों ने सफलता हासिल की। रायडु का नाकाम रहना इसलिए उल्लेखनीय है कि परफॉर्मेंस के पैमाने पर वह कहीं से भी अनफिट नजर नहीं आते। डेढ़ साल बाद भारतीय वनडे टीम में वापसी करने वाले रायडु ने हाल में आईपीएल में चेन्नई की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई थी, साथ ही आईपीएल के कुल 16 मैचों में एक शतक और तीन अर्धशतकों की बदौलत 602 रन बनाए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए बाहर किया जा सकता है कि वह शारीरिक फिटनेस के किसी आंकड़े को छू नहीं सका। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के परिप्रेक्ष्य में एक अन्य अहम सवाल यह है कि क्या फिटनेस के ऐसे ही पैमाने खेल से बाहर दूसरे कार्यक्षेत्रों में नहीं अपनाए जाने चाहिए।

भारतीय क्रिकेट में पिछले दो वर्षों से लागू किए गए फिटनेस टेस्ट यो-यो की शुरुआत काफी विवादास्पद रही थी। अनिल कुंबले के क्रिकेट कोच बनने के बाद पहली बार हुए इस टेस्ट में मशहूर क्रिकेटर सुरेश रैना न्यूजीलैंड दौरे में चयनित होने के बावजूद यो-यो टेस्ट में फेल होने के कारण शुरुआती दो मैचों के लिए अनफिट करार दिए गए थे। यह टेस्ट मैदान पर शारीरिक-मानसिक फिटनेस के अलावा खिलाड़ी की दिमागी एकाग्रता और त्वरित एक्शन को मापता है। गौरतलब है कि भारत में क्रिकेटरों के लिए इस टेस्ट को पास करने का मानक बेहद आसान 16.1 है, जबकि पड़ोसी पाकिस्तान में 17.4, वेस्टइंडीज में 19 और न्यूजीलैंड में सर्वाधिक कठिन मानक यानी 20.1 है। सामान्य नजरिये से देखें तो इस टेस्ट में दो किलोमीटर की दौड़ आठ मिनट में पूरी करनी होती है, लेकिन इस दौड़ में किसी खिलाड़ी की दक्षता इससे नापी जाती है कि क्या वह 30 सेकेंड में बॉलिंग करने, थ्रो करने, स्टंप पर फेंकने के बाद अगली बॉल फेंकने के लिए तैयार है।

यूं दूसरे खेलों में भी इसी तरह के कुछ टेस्ट खिलाड़ियों की फिटनेस का स्तर जांचने के लिए किए जाते हैं, पर युवाओं की बड़ी आबादी वाले देश में अब असल में इस तरह के टेस्ट की जरूरत हर तरह के कार्यक्षेत्र में पड़ रही है। मुद्दा सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जैसे आयोजनों को सफल बनाना या फिर युवाओं को अपने कार्यक्षेत्र में सक्रिय करना ही नहीं है, बल्कि यह है कि हमारे देश में युवा और मध्यवर्गीय आबादी कई ऐसी बीमारियों का शिकार बन रही है जो उसे आलसी बनाने वाली लाइफ स्टाइल की देन है। खासतौर से युवा आलसी होकर दिल के रोगों तक की चपेट में आ रहे हैं।

इसमें भरपूर संदेह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्रिकेटर विराट कोहली और केंद्रीय खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आदि के जरिये जो फिटनेस चैलेंज इधर दिया गया है, वह हमारे आम युवाओं में कोई ज्यादा प्रेरणा जगा पाएगा। मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया के मारे युवा वर्ग के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती बदली लाइफ स्टाइल के कारण पैदा हुई बीमारियों और आलसपन से निजात पाना है। यह जरूरी क्यों हुआ, इसकी बानगी हाल के वे कुछ अध्ययन और रिपोर्ट दे रही हैं, जिनके मुताबिक युवाओं का बड़ा तबका दिल के रोगों के अलावा डायबिटीज, डिप्रेशन और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों की चपेट में आ रहा है। देश के युवा जिस लाइफ स्टाइल डिस्ऑर्डर की गिरफ्त में आए हैं, उसके पीछे कामकाज के तनाव, खानपान की गलत आदतें, कंप्यूटर, मोबाइल आदि पर देर तक काम करना, स्मोकिंग, तंबाकू, शराब की लत और पर्यावरण प्रदूषण जिम्मेदार हैं। लेकिन जिन बाकी चीजों का असर युवाओं पर पड़ रहा है, उसके लिए उन्हें यो-यो टेस्ट जैसे कठिन उपायों की तरफ बढ़ना होगा तभी वे राहत महसूस कर पाएंगे। पिछले साल आई बॉडी बर्डन रिपोर्ट में कहा गया था कि जीवनशैली और खराब पर्यावरण के कारण हमारे देश में 2005 से 2015 के बीच मोटापे से जूझने वालों की संख्या दोगुनी हुई है। इनमें 15 से 49 आयु वर्ग के लोगों में 20.7 फीसदी महिलाएं और 18.6 प्रतिशत पुरुष ओवरवेट हैं। इस तरह 18 साल से ऊपर के लोगों में 10 फीसदी लोग दिमागी बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसके अलावा भारत में होने वाली मौतों में 26 फीसदी दिल के रोगों से होती हैं, जिनमें युवाओं की भारी तादाद है। शहरों में कुछ लोगों ने जिम जाने, सुबह पार्क में टहलने या योग करने का रास्ता निकाला है,लेकिन यह सब पर्याप्त नहीं है। विशेषज्ञों और डायटिशन के अनुसार फिट रहने के लिए रोज 10 हजार कदम चलना जरूरी है। आपको पूरे दिन एक्टिव रहना होगा। इसके लिए हमें अपने रहन-सहन के साथ अपनी सोच भी बदलनी होगी। चिकित्सक कहते हैं कि लोगों को चलने-फिरने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इसी तरह दफ्तरों का वर्क कल्चर ऐसा होना चाहिए कि लोगों को एक्टिव (सक्रिय) रहने का मौका मिले। दफ्तरों में सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि पानी की अपनी बोतल भरकर लाने, फोटोकॉपी निकालने जैसे छोटे-मोटे काम भी खुद करने की आदत डालनी होगी। इसके लिए सबसे पहले इस सोच से मुक्त होना होगा कि शिक्षित और समृद्ध व्यक्ति अपने काम दूसरों से करवाता है। साफ है कि अगर युवाओं के इस देश को सेहत के मामले में कोई बाजी मारनी है तो सामाजिक और कामकाजी जीवन में एक नए किस्म का यो-यो टेस्ट अपने लिए विकसित करना होगा जो शरीर का आलस्य खत्म कर उसे फुर्तीला बनाता है।

छावनी क्षेत्र

तार्किक नहीं किलेबंदी

रणधीर तेजा चौधरी

छावनी क्षेत्रों में सड़कों पर नागरिकों की आवाजाही प्रतिबंधित करने संबंधी चर्चा विवाद का रूप लेती दिखाई दी तो रक्षा मंत्रालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कुछेक सड़कें प्रतिबंधित की जा सकती हैं, सभी नहीं। और वह भी स्थानीय अथॉरिटी की अनुमति से। लेकिन सैनिक अधिकारियों के परिवार और सेवानिवृत्त सैनिक रक्षा मंत्रालय के फैसले के विरोध में उतर आए। सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर इस फैसले के खिलाफअभियान सा छेड़ दिया। कुछ अधिकारियों की पत्नियां रक्षा निर्मला सीतारमन से मिलीं। उन्हें उम्मीद थी कि रक्षा मंत्रालय इस दिशा में कुछ करेगा। लेकिन रक्षा मंत्री के बयान और थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत के रुख से लगता है कि रक्षा मंत्रालय के आदेश में शायद ही बदलाव हो। इस फैसले का विरोधकरने वालों को लगता है कि सभी सड़कें खोल दिए जाने से सैन्य प्रतिष्ठानों और सैनिकों के परिवारों की सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाएगी। उन्हें आतंकी घटना का अंदेशा है। फिर उन्हें यह भी लगता है कि भू-माफिया रक्षा भूमि पर अतिक्रमण कर सकता है। सरकार का कहना है कि उसका फैसला सैन्य ठिकानों पर लागू नहीं होता। यह केवल छावनी क्षेत्रों के लिए ही है। इसलिए इसका विरोधकरने का कोई तुक नहीं है। गौरतलब है कि देश में 467 सैन्य ठिकाने हैं, और 62 छावनियां। छावनी क्षेत्र देश के सर्वाधिक प्रमुख शहरों में बेशकीमती भूमि पर आबाद हैं। रक्षा भूमि पर अतिक्रमण जैसी बात में भी कोईदम नहीं है, क्योंकि सरकार द्वारा संसद में पेश जानकारी के मुताबिक, देश में अभी 17.57 लाख एकड़ रक्षा भूमि है, जिसमें से केवल 1.57 लाख एकड़ भूमि ही छावनियों में है।

सरकार ने संसद में बताया कि इसमें से मात्र दस हजार एकड़ भूमि का ही अतिक्रमण हुआ है। बीते साल दिसम्बर महीने में पुणो से सांसद अनिल शिरोले ने सरकार को लिखा था कि कोरेगांव पार्क स्थित कब्रिस्तान तक जाने वाली सड़क को सेना बंद कर दिया था। इससे घोरपड़ी में रहने वालों के लिए परेशानी हो गई। नासिक के सांसद हेमंत गोडसे ने बताया कि देवलाली छावनी में महसोबा मंदिर तक जाने वाली सड़क को बंद करने की बाबत बताया। साथ ही इस क्षेत्र में मुस्लिम और बोहरा समुदायों के कब्रिस्तानों तक जाने वाली सड़कों को बंद किए जाने के बारे में भी बताया था। इसी प्रकार मल्काजगरी से सांसद मल्ला रेड्डी ने बताया था कि सकिंदराबाद छावनी क्षेत्र के हॉली ट्रिनिटी चर्च को बंद कर दिया गया। और यह सब आतंकी गतिविधियों के अंदेशे में किया गया। छावनियों की बंदोबस्ती छावनी बोर्ड करते हैं। ये निर्वाचित निकाय छावनी अधिनियम के तहत अपना कामकाज करते हैं। दरअसल, हमारे सैन्य प्रशासन की मानसिकता अभी भी बदली नहीं है। औपनिवेशिक काल में सेना सोचती थी-आसपास किलेबंदी करने में ही सुरक्षा है। संभवत- वैसा ही आज भी सोचती है। छावनी की हर सड़क, हालांकि ये सार्वजनिक हैं, पर चेकिंग से आम नागरिक की असुविधा पर उसका ध्यान नहीं होता। सेना के अधिकारी इस तरह से क्यों नहीं सोचते कि ऐसा करके तो वे न केवल खुद को अलग-थलग कर लेंगे, बल्कि अपने ही लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में व्यवधान पैदा कर देंगे। छावनी क्षेत्रों में लिएस्कूल, अस्पताल, बाजार, पार्क आदि जैसी नागरिक सुविधाएं 1923 में छावनी अधिनियम लागू होने के समय ही मुहैया करा दी गई थीं। सैनिक परिवारों के साथही नागरिकों के लिए भी। देश की छावनियों में छावनी बोडरे द्वारा 203 स्कूल, 88 अस्पताल और 46 व्यावसायिक प्रशिक्षर केंद्र संचालित किए जाते हैं। ये इदारे छावनी क्षेत्रों में आबाद 23 लाख की नागरिक आबादी को ये सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। इन क्षेत्रों में आम लोगों के बंगले और सिविलियन इलाके छावनी अधिनियम लागू होने के समय से ही मौजूद हैं। यहां रहते इनकी कई पीढ़ियां गुजर गई। मजे की बात यह कि इन्हें क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों से कोईलेना देना नहीं होता। सेना क्षेत्र में इनसे किसी खतरे की सोची भी नहीं जा सकती। इस हवाले से आवाजाही प्रतिबंधित करना गले नहीं उतरता। छावनियों में सेवारत सैन्य अधिकारियों के बंगले, सैनिकों के क्र्वाटर, रेजिमेंटल सेंटर, यूनिट लाइंस और सैन्य कार्यालय हैं। कभी नहीं सुना कि सैन्य कार्यालयों के कामकाज पर सिविलियन के कारण असर पड़ा हो। दरअसल, सेना के कुछ पूर्व अधिकारी छावनियों को विशेषाधिकार दिए जाने जैसी मांग कर रहे हैं।

115 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ सेंसेक्स

मुंबई। जब सुबह शेयर बाजार खुला तो उसमें उछाल देखा गया, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने ही बढ़त बनाते हुए कारोबार की शुरुआत की लेकिन कारोबार की समाप्ति पर घरेलू शेयर बाजार बढ़त बनाए रखने में नाकामयाब रहा और कारोबार की समाप्ति पर ये औंधे मुंह जा गिरा। गिरावट के इस माहौल में कारोबार की समाप्ति पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का तीस शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 114.94 अंक यानि 0.32 प्रतिशत की गिरावट के साथ 35,432.39 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स की तरह ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के पचास शेयरों वाले निफ्टी पर भी कारोबार की समाप्ति पर गिरावट हावी रही और ये लाल निशान पर पहुंचकर 30.95 अंक यानि 0.29 प्रतिशत की गिरावट के साथ 10,741.10 के स्तर पर बंद हुआ। गौरतलब है कि कल के कारोबार के दौरान पिछले दो दिन से जारी गिरावट थम गई। बैंकिंग, धातु और रीयल्टी कंपनियों के शेयरों में लिवाली का जोर रखा। कल के कारोबार के दौरान शेयर बाजार में काराबोर की शुरुआत बढ़त के साथ हरे निशान पर हुई और कारोबार की समाप्ति पर ये बढ़त को बरकरार रखता हुआ हरे निशान पर ही बंद हुआ। काराबोर की शुरुआत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का तीस शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 42.87 अंक की बढ़त के साथ 35,329.61 के स्तर पर खुला और काराबोर की समाप्ति पर ये 260.59 अंक यानी 0.74 प्रतिशत बढ़कर 35,547.33 अंक पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का पचास शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स निफ्टी भी काराबोर की शुरुआत में 24.2 अंक की बढ़त के साथ 10,734.65 के स्तर पर खुला और काराबोर की समाप्ति पर ये 61.60 अंक यानी 0.58 प्रतिशत चढ़कर 10,772.05 अंक पर बंद हुआ।

बड़ी गिरावट के साथ फिर सस्ता हुआ सोना, ज्वेलरी खरीदने का सही समय

नई दिल्ली। कमजोर वैश्विक रुख के बीच स्थानीय आभूषण विनिर्माताओं और फुटकर विक्रेताओं की मांग घटने से दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना गुरुवार को 145 रुपये टूटकर 31,570 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. हालांकि, औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं की छिटपुट मांग के बीच चांदी 41 हजार रुपये प्रति किलोग्राम के पुराने स्तर पर ही बनी रही. बाजार कारोबारियों ने कहा कि आभूषण विनिर्माताओं की मांग घटने से सोने की कीमतों में गिरावट आई.

निवेश के लिए सोने की मांग घटी

इसके अलावा कमजोर वैश्विक रुख और डॉलर में मजबूती से निवेश के सुरक्षित विकल्प के रूप में सोने की मांग घटी. वैश्विक स्तर पर सिंगापुर में गुरुवार को सोना 0.17 प्रतिशत के नुकसान से 1,265.66 डॉलर प्रति औंस पर आ गया. चांदी 0.23 प्रतिशत के नुकसान से 16.24 डॉलर प्रति औंस रह गई. राजधानी में सोना 99.9 प्रतिशत और 99.5 प्रतिशत शुद्धता 145-145 रुपये के नुकसान से क्रमशः 31,570 रुपये तथा 31,420 रुपये प्रति दस ग्राम रह गया.

गिन्नी के भाव में बदलाव नहीं

आठ ग्राम की गिन्नी के भाव 24,800 रुपये प्रति आठ ग्राम पर कायम रहे. वहीं दूसरी ओर छिटपुट मांग के बीच चांदी हाजिर 41 हजार रुपये प्रति किलोग्राम पर कायम रही. साप्ताहिक डिलिवरी के भाव हालांकि 240 रुपये टूटकर 39,490 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गए. चांदी सिक्का लिवाल 74 हजार रुपये तथा बिकवाल 75 हजार रुपये प्रति सैकड़ा पर कायम रहा.

टाटा मोटर्स की इस वित्त वर्ष 50 वाणिज्यिक वाहन पेश करने की योजना

नई दिल्ली। वाहन बनाने वाली कंपनी टाटा मोटर्स की योजना इस वित्त वर्ष में करीब 50 वाणिज्यिक वाहन पेश करने की है। कंपनी का लक्ष्य वाणिज्यिक वाहन क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करना है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी। कंपनी ने 2017-18 के दौरान वाणिज्यिक एवं यात्री वाहन श्रेणी में लागत

खर्च में कटौती के कदम उठाकर करीब 1,900 करोड़ रुपए की बचत की थी। कंपनी इस वित्त वर्ष में ऐसी बचत का लक्ष्य पाना चाहती है। कंपनी चालू वित्त वर्ष में वाणिज्यिक वाहन खंड में 1,500 करोड़ रुपए के करीब पूंजीगत खर्च भी करने वाली है। इस राशि का इस्तेमाल शोध एवं विकास , क्षमता विस्तार तथा एक अप्रैल 2020 तक भारत स्टेज छह (बीएस-छह) के उत्सर्जन प्रावधानों की सरकारी समयसीमा के अनुपालन पर किया जाएगा। टाटा मोटर्स के अध्यक्ष (वाणिज्यिक वाहन कारोबार) गिरीश वाघ ने कहा , पिछले साल हमने संस्करणों तथा बदले स्वरूपों समेत 50 से अधिक नए उत्पाद पेश किए। हम इस वित्त वर्ष में भी उत्पाद पेश करने के मामले में इसी रफ्तार को जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि देश में नए उत्पाद पेश करने की दीर्घकालिक रणनीति के तहत कंपनी उत्पाद नियोजन की बेहद मजबूत प्रणाली तैयार करने की प्रक्रिया में है। वाघ ने कहा, इस निकाय का जोर सिर्फ भविष्य पर रहेगा तथा यह उपभोक्ताओं की बदलती जरूरतों , वैश्विक बाजार की परिस्थिति और कारकों के बदलाव पर नजर रखेगा। उन्होंने कहा कि निकाय को पंचवर्षीय उत्पाद योजना तैयार करने का काम दिया गया है। -एजेंसी

फल-सब्जियों के कचरे से बनेगा बसों का ईंधन, प्रधानमंत्री करेंगे शुरूआत

इंदौर (एजेंसी)

कचरे से मुक्ति के साथ इससे कमाई का संदेश देने वाले नवाचारी संयंत्र की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यहां 23 जून को औपचारिक शुरूआत करेंगे। राष्ट्रीय स्वच्छता रैंकिंग में लगातार दूसरे साल अव्वल रहे शहर में इस संयंत्र के जरिये फल-सब्जियों के कचरे से बायो-सीएनजी बनायी जायेगी और फिर इस हरित ईंधन से लोक परिवहन वाहनों को दौड़ाया जायेगा। इंदौर नगर निगम (आईएमसी) के आयुक्त आशीष सिंह ने आज बताया कि प्रधानमंत्री अपने एक दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे के तहत स्थानीय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित 'शहरी विकास महोत्सव' में हिस्सा लेंगे।

इस दौरान वह अन्य सरकारी योजना-परियोजनाओं के साथ फल-सब्जियों के कचरे से बायो-सीएनजी बनाने के संयंत्र का ई-उद्घाटन करेंगे। उन्होंने बताया कि आईएमसी ने एक निजी कम्पनी की मदद से देवी अहिल्याबाई होलकर फल-सब्जी मंडी में शहर का पहला बायोमीथेनाइजेशन प्लांट लगाया है। इस संयंत्र के जरिये हर रोज फल-सब्जियों के 20 टन अपशिष्ट को 1,000 किलोग्राम बायो-सीएनजी में बदला जा सकता है। सिंह ने कहा, 'शुरूआत में हम अपनी 63 सिटी बसों (शहरी लोक परिवहन बस) में से करीब 15 बसों को बायो-सीएनजी से दौड़ायेंगे। फिलहाल इन बसों में सामान्य सीएनजी इस्तेमाल की जा रही है।' उन्होंने बताया कि बायोमीथेनाइजेशन प्लांट चलाने वाली कंपनी से हुए अनुबंध के तहत आईएमसी को बायो-सीएनजी काफी रियायती मूल्य पर प्रदान की जायेगी और यह सामान्य सीएनजी के मुकाबले सस्ती पड़ेगी। नतीजतन स्थानीय निकाय के ईंधन बिल में कटौती होगी। लोक परिवहन बसों में हरित ईंधन के इस्तेमाल से पर्यावरण की भी हिफाजत होगी। एक अनुमान के मुताबिक कोई 35 लाख की आबादी वाले इंदौर में हर रोज तकरीबन 1,100 टन कचरे का अलग-अलग तरीकों से सुरक्षित निपटारा किया जाता है। इसमें 650 टन गीला कचरा और 450 टन सूखा कचरा शामिल है।

इस बीच, मध्यप्रदेश के जनसम्पर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री यहां 23 जून को आयोजित कार्यक्रम में 'स्वच्छ सर्वेक्षण 2018' की अलग-अलग श्रेणियों में विजेता शहरों को पुरस्कृत भी करेंगे जिनमें मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल शामिल हैं। इसके साथ ही, वह अलग-अलग सरकारी योजनाओं के तहत 4713.75 करोड़ रुपये की लागत के विभिन्न कार्यों का ई-लोकार्पण करेंगे। अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी शहरी लोक परिवहन योजना 'सूत्र सेवा' का शुभारंभ भी करेंगे। पहले चरण में इस किफायती बस सेवा के जरिये सूबे के 20 चुनिंदा शहरों को जोड़ा जायेगा। शुरूआत में इंदौर, भोपाल, जबलपुर, छिन्दवाड़ा, गुना और भिण्ड से 127 बसों का संचालन किया जायेगा।

कच्चे तेल पर अंतरराष्ट्रीय बैठक के पहले सऊदी अरब, ईरान के बीच तनातनी

वियना (एजेंसी)।

सऊदी अरब ने कहा है कि वह विश्व बाजार में कच्चे तेल आपूर्ति में कमी की स्थिति को टालने के लिए जो जरूरी हो करेगा। इस बयान से तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक की तनाव के माहौल में होने जा रही बैठक से पहले ईरान के साथ सऊदी अरब के टकराव का मंच तैयार हो गया है। सऊदी अरब के शहजादे और ऊर्जा राज्य मंत्री अब्दुल अजीज बिन सलमान ने वियना में एक बैठक में कहा कि बाजार की स्थिरता को बनाए रखने के लिए जो जरूरी होगा वह हम करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि तेल आपूर्ति में कमी नहीं हो। उन्होंने कहा कि कई उपभोक्ता देश संभावित तेल की कमी होने के आसार से चिंतित हैं '', उन्होंने कहा कि आने वाले महीनों में वैश्विक तेल मांग बढने की उम्मीद है। ओपेक के गैर - सदस्य देश रूस के साथ साथ जगत का सम्राट देश माने जाने वाला सऊदी अरब जोर शोर से प्रयास कर रहे हैं कि ओपेक देशों के तेल मंत्रियों और मित्र

देशों के बीच उत्पान सीमा में ढ़ील देने पर इस सप्ताह सहमति कामय हो जाए। उत्पादन स्तर घटाए जाने के कारण वर्ष 2016 के बाद से तेल कीमतें दोगुना हो गई हैं। सऊदी अरब पर अमेरिका का दबाव है। इससे ईरान उसका कड़ा विरोध कर रहा है। अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंतराष्ट्रीय समझौते से हट गया है और उसने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसी घटना में बोलते हुए, ईरानी तेल मंत्री बिजान नामदार जांगानेह ने तेल उत्पादन में वृद्धि के लिए अपने देश के प्रतिरोध को दोहराया और ट्रंप पर ओपेक का राजनीतिकरण करने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

यात्रियों ने एयर एशिया के कर्मचारियों पर लगाया दुर्व्यवहार का आरोप

गुवाहाटी। एयर एशिया की एक उड़ान में सवार कुछ यात्रियों ने विमान कर्मचारियों के खिलाफ दुर्व्यवहार आरोप लगाया है। यह उड़ान कोलकाता से बागडोगरा जा रही थी और करीब साढ़े चार घंटे देर थी। एक यात्री ने यह दावा किया। विमान में सवार इंडियन ऑयन कॉरपोरेशन के कार्यकारी निदेशक (पश्चिम बंगाल) दीपांकर रे ने कहा कि कर्मचारियों ने यात्रियों के साथ बेहद गैर - पेशेवर तरीके से व्यवहार किया और उन्हें विमान से उतर जाने को कहा। इसके बाद दोनों पक्षों में कहा-सुनी भी हो गयी। रे ने कहा, 'विमान सुबह के नौ बजे उड़ान भरने वाली थी और शुरू में आधे घंटे देर थी। बोर्डिंग के बाद हमलोग डेढ़ घंटे विमान में ही बिना खाना-पानी के बैठे रहे।' इसके बाद विमान के कप्तान ने बिना कारण बताये सभी को उतर जाने को कहा। जब यात्रियों ने बाहर भारी बारिश के कारण उतरने से मना किया तो कप्तान ने यात्रियों को डराने के लिए पूरी तेजी से एसी चला दिया। इससे विमान के अंदर डरावना दृश्य पैदा हुआ और चारों तरफ धुंध छा गयी। लोगों को घुटन होने लगी। उन्होंने कहा कि कई महिलाओं एवं बच्चों को इससे उल्टियां होने लगीं। संपर्क किये जाने पर एयर एशिया ने विमान देर होने की बात स्वीकार की तथा अफसोस जाहिर किया। कंपनी ने इसके बाद बयान भी जारी किया।

मूडीज ने पाकिस्तान की साख को स्थिर से घटाकर नकारात्मक किया

कराची। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर इंटरनेशनल ने पाकिस्तान की साख को घटाकर स्थिर से नकारात्मक कर दिया है। रेटिंग एजेंसी ने विदेशों के साथ कारोबार की दृष्टि से देश की कमजोरी और आरक्षित विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव को देखते हुए उसकी रेटिंग कम की है। मूडीज ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि पाकिस्तान में विदेशों से धन की आवक कम हो गयी है और विदेशी मुद्रा भंडार नीचे आ गया है और अगले एक से डेढ़ साल में इसे भर पाना संभव नहीं है। पाकिस्तान का साख परिदृश्य ऐसे समय घटाया गया है जबकि यहां 25 जुलाई को आम चुनाव होने वाले हैं। मूडीज ने कहा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रेटिंग में बदलाव का फैसला बाहरी जोखिम बढ़ने की वजह से लिया गया है। मौजूदा भुगतान संतुलन दबाव की वजह से विदेशी मुद्रा के सुरक्षित भंडार के लिए भी जोखिम है। बयान में कहा गया है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार कम होने से उसके लिए विदेशी देनदारियां पूरी करने के लिए सस्ती दर पर कर्ज जुटाना मुश्किल हो गया है इससे सरकार की नकदी की स्थिति पर जोखिम है। पिछले सप्ताह से पाकिस्तानी रुपये पर भी दबाव है और यह 124 रुपये प्रति डॉलर तक टूट चुका है। करेंसी एक्सचेंज डीलरों का कहना है कि डॉलर की कमी हो गई है। पिछले सप्ताह तक पाकिस्तानी रुपया 115.5 रुपये प्रति डॉलर पर था।

ट्रंप के होटल का शराब लाइसेंस रद्द करने की मांग, ट्रंप के चरित्र को बताया खराब

वाशिंगटन (एजेंसी)।

अमेरिका के धार्मिक नेताओं और पूर्व न्यायाधीशों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चरित्र और ईमानदारी पर सवाल उठाते हुए उनके होटल ट्रंप इंटरनेशनल होटल का शराब का लाइसेंस रद्द करने की मांग की है. अल्कोहलिक बेवरेज कंट्रोल बोर्ड को भेजी गई शिकायत में कहा गया है, 'ट्रंप इंटरनेशनल होटल के वास्तविक मालिक डोनाल्ड ट्रंप अच्छे चरित्र के इंसान नहीं हैं. स्थानीय नियमों के अनुसार शराब लाइसेंस के लिए धारक का अच्छे चरित्र का होना अनिवार्य है.'

शिकायत में आगे कहा गया, 'बहरहाल

बोर्ड द्वारा चरित्र की जांच लाइसेंस के आवेदन या नवीकरण के समय की जाती है, लेकिन ट्रंप के खराब व्यवहारों से यह आवश्यक हो जाता है कि बोर्ड अभी उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करे.' शिकायत पर हस्ताक्षर करने वालों में पूर्व न्यायाधीश हेनरी कैनेडी जूनियर और जोआन गोल्डफ्रैंक, धार्मिक नेता विलियम लामार चतुर्थ, जेनिफर बटलर और टिमोथी टी बडी तथा रब्बी आरोन पोटेक एवं रब्बी जैक मोलिन शामिल हैं.

मैरीलैंड और वाशिंगटन राज्य के वकीलों ने कहा, 'धनी और शक्तिशाली लोगों को कोई वैधानिक छूट नहीं दी गई है.' उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप इंटरनेशनल होटल के जरिये अवैध भुगतान लिया गया है. हालांकि ट्रंप के वकील ने आरोप का विरोध करते हुए कहा कि सारे भुगतान पूरी तरह वैधानिक हैं क्योंकि ट्रंप ने इनके बदले में कोई पेशकश नहीं की. इस मामले में जुलाई के अंत तक फैसला आने का अनुमान है.

सेबी ने आईपीओ नियमों में बदलाव किए

नयी दिल्ली (एजेंसी)।

बाजार नियामक सेबी ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) में बदलाव किया है। इससे कंपनियां आईपीओ का प्राइस बैंड ऑफर शुरू करने के दो पहले घोषित कर सकती है। अभी प्राइस बैंड आईपीओ आने के पांच दिन पहले घोषित करना पड़ता है। सेबी ने गुरुवार को बोर्ड की बैठक में इन बदलावों को मंजूरी दी। बाजार नियामक सेबी ने अधिग्रहण नियमों में कुछ बदलावों को मंजूरी दे दी। इसके तहत इकाइयों को खुली पेशकश में प्रस्तावित खरीद दर के संशोधन के लिए निविदा की अविध के दौरान अतिरिक्त समय मिलेगा। इसके साथ ही पुनर्खरीद नियमों में भी संशोधन किया जाएगा। सेबी ने एक बयान में कहा है,' शेयर निविदा प्रक्रिया अवधि की शुरुआत से एक दिन पहले तक खुली पेशकश कीमत में संशोधन के लिए अतिरिक्त समय देने का फैसला किया गया है। नियामक का कहना है कि इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य सम्बद्ध कानून की भाषा को सरल बनना, अनावश्यक प्रावधानों को हटाना भी है। इसके लिए सेबी (अधिग्रहण तथा शेयरों का प्यापक अधिग्रहण) नियम 2011 में बदलाव किए जाएंगे।

व्हाट्सएप लीक मामले में चार रिपोर्ट मिलीं: बाजार नियामक सेबी को सोशल मीडिया मंच व्हाट्सएप के जरिए कीमत संवेदी सूचनाएं लीक करने के मामले में अब तक चार रिपोर्ट मिली हैं। नियामक इस मामले में आगे जांच कर रहा है। सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी ने गुरुवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कंपनियों को अपने स्तर पर जांच करने को कहा गया था। इस मामले में लगभग एक दर्जन फर्म सेबी के जांच दायरे में हैं। सेबी ने इस मामले में एचडीएफसी बैंक , टाटा मोटर्स , एक्सिस बैंक व बाटा इंडिया के खिलाफ शुरुआती आदेश जारी किए थे। इन कंपनियों से विभागीय जांच कर नियामक को रिपोर्ट देने को कहा गया था।

सेबी को कोचर मामले में आईसीआईसीआई बैंक से जवाब नहीं मिला

मुंबई । भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को अभी तक आईसीआईसीआई बैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर पर आरोपों के बारे में बैंक से कोई जवाब नहीं मिला है. सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी दी. सेबी के अलावा सीबीआई सहित कई अन्य एजेंसियां कोचर और उनके परिवार से संबंधित मामले में गड़बड़ियों की जांच कर रही हैं. यह मामला वीडियोकॉन समूह और कुछ अन्य इकाइयों को कर्ज देने से संबंधित है. सेबी के निदेशक मंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में त्यागी ने कहा, 'हमें अभी तक आईसीआईसीआई बैंक से जवाब नहीं मिला है.' जो मामले जांच के दायरे में हैं उनमें बैंक द्वारा 2012 को वीडियोकॉन समूह को दिया गया कर्ज और ऋण के पुनर्गठन में कोचर के परिवार के सदस्यों की भूमिका. कोचर और उनके परिवार के सदस्यों पर कुछ इकाइयों को दिए गए कर्ज में लेनदेन और हितों के टकराव का आरोप है. आईसीआईसीआई बैंक ने सोमवार को घोषणा की थी कि इस मामले में बाहरी जांच पूरी होने तक चंदा कोचर अवकाश पर जा रही हैं. संदीप बख्शी को बैंक का मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है.

एक से ज्यादा पेन कार्ड रखने का ये बड़ा नुकसान नहीं जानते होंगे आप

नई दिल्ली (एजेंसी)।

मौजूदा समय में पेन कार्ड जरूरी आइडेंटी डाक्यूमेंट हो गया. पैन 18 साल से ऊपर की उम्र वाले भारतीयों को वेलिड सोर्स ऑफ इनकम के लिए जारी किया जाता है. पैन कार्ड को इनकम टैक्स के एक्ट 1961 के अधीन जारी किया जाता है. सेक्शन 139 के तहत 18 साल से ऊपर की आयु वाले भारतीयों के लिए पैन कार्ड जरूरी है. पैन कार्ड के जरिए सरकार के पास प्रत्येक व्यक्ति का फाइनेंशियल डाटा रहता है. इसके अलावा कॉरपोरेट कंपनियों का टैक्स रिलेटिड कामों के लिए पैन कार्ड बनाया जाता है. 10 डिजिट के परमानंट अकाउंट नंबर अल्फा-न्यूमेरिक नंबर होते हैं. बड़ी संख्या में टैक्स पे करने वाले ऐसे लोग और कॉरपोरेट कंपनियां हैं जिनके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड मिल जाते हैं. कई बार एक से ज्यादा पैन कार्ड लोग जानबूझकर या अंजाने में भी बनवा लेते हैं. लेकिन एक से ज्यादा पैन कार्ड के नुकसान के बारे में शायद ही आपको पता हो. अगर आप लोन के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं तो एक से ज्यादा पैन कार्ड रखने पर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होनी मुश्किल हो सकती है. आगे पढ़िए एक से ज्यादा पैन कार्ड रखने पर आपको क्या नुकसान हो सकता है.

पेनाल्टी: सेक्शन 272क्क के तहत इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दो पैन कार्ड रखने पर आपके ऊपर पेनाल्टी (जुर्माना) लगाया जा सकता है. यह पेनाल्टी 10 हजार रुपये तक हो सकती है. लेकिन टैक्स फ्रॉड या टैक्स अपवंचन के मामले में यह ज्यादा भी हो सकती है.

मुकदमा: दो पैन कार्ड रखने पर आपके ऊपर मुकादमा हो सकता है. यह मुकदमा टैक्स बचाने, मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स फ्रॉड से जुड़ा हो सकता है. इंडियन टैक्स एंड मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत आपका इस तरह का अपराध आपको मुश्किल में डाल सकता है.

सूरत। शहर में विश्व योग दिवस मनाया गया। जिलास्तरीय कार्यक्रम सरथाणा स्थित कन्वेंशन हॉल में हुआ। जिसमें गुजरात के मंत्री गणपत वसावा, सांसद सीआर पाटिल, विधायक झंखना पटेल, विवेक पटेल, मेयर जगदीश पटेल, स्थायी समिति अध्यक्ष अनिल गोपलानी समेत पदाधिकारी और बड़ीं सख्या में शहर वासी उपस्थित रहे। शहर में पुलिस बल द्वारा भी योग दिवस पर योग का कार्यक्रम किया गया जिसमें बड़ीं संख्या में पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस जवानों ने योग किया। योग दिवस पर स्कुली बच्चों द्वारा स्कूल में योग किया गया। शहर के वेड रोड़ स्थित गुरुकुल में भी योग किया गया।

अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडिय में चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बड़ी संख्या में लोगों के साथ योगा करते मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री पीपी चौधरी और अहमदाबाद की महापौर बिजल पटेल।

गुजरात कांग्रेस में अनदेखी किए जाने से वरिष्ठ नेताओं में नाराजगी बढ़ी

अहमदाबाद (ईएमएस)। गुजरात प्रदेश कांग्रेस में आंतरिक कलह तेज हो गई है। आरोप है कि वरिष्ठ नेताओं को नजरअंदाज कर युवाओं को महत्वपूर्ण पद सौंपे जा रहे हैं। मेहसाणा के पूर्व सांसद जीवाभाई पटेल के कांग्रेस छोड़ने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में नाराजगी बढ़ी है। जसदण के विधायक कुंवरजी बावलिया के बाद अब खंभालिया के विधायक विक्रम माडम ने नाराजगी जाहिर की है। कुंवरजी बावलिया ने कांग्रेस से इस्तीफा देने की खबरों को अफवाह करार दिया और कहा कि मैं किसी नाराज नहीं हूं। मैं कांग्रेस था और उसी में रहूंगा। हांलाकि उन्होंने स्वीकार किया कि कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी की जा रही है और इसी मुद्दे पर वे पार्टी हाईकमांड से पेशकश करेंगे। वहीं विक्रम माडम का कहना है कि वे अपनी नाराजगी पार्टी नेताओं के समक्ष बयां करेंगे। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के एक गुट ने युवा नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। परेश धानाणी को गुजरात विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और अमित चावड़ा को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से वरिष्ठ नेताओं में नाराजगी बढ़ने लगी थी। अब जीवाभाई पटेल के इस्तीफे और विक्रम माडम की नाराजगी के बाद कांग्रेस में आंतरिक कलह तेज हो गई है। विक्रम माडम के मुताबिक इतनी बड़ी पार्टी में सब कुछ ठीक होना संभव नहीं है। यदि सब कुछ ठीक होता तो जिला पंचायत और तहसील पंचायतें कांग्रेस के हाथ नहीं निकलती। इस बात का अफसोस है, परंतु कभी मीडिया के सामने अपनी पीड़ा बयां नहीं की। लेकिन सच्चे और कर्त्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय होने पर खामोश रहना भी ठीक नहीं है और उसके बारे में अब पार्टी के समक्ष शिकायत करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात कांग्रेस में फिर एक बार असंतोष स्वर मुखर होने लगे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी में युवाओं को अधिक तवज्जो दे रहे हैं, जिसे लेकर वरिष्ठ नेताओं में नाराजगी बढ़ रही है। जूनियर नेताओं को महत्वपूर्ण पद दिए जाने से सिनियर नेताओं में नाराजगी है। जीवाभाई पटेल, कुंवरजी बावलिया और विक्रम माडम के बाद अन्य वरिष्ठ नेताओं में नाराजगी है। हांलाकि कई नेताओं ने खुलकर नाराजगी व्यक्त नहीं की है परंतु संगठन में वरिष्ठ नेताओं से सलाह मशविरा नहीं करने की शिकायतें की जाने लगी हैं। नाराज नेताओं की मांग है कि लोकसभा चुनाव से पहले वरिष्ठ नेताओं को मार्गदर्शन लेने के साथ ही उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपे जाए। हांलाकि यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी सामने आई है।

26 व 30 जून की अहमदाबाद-जम्मूतवी एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलेगी

अहमदाबाद (ईएमएस)। उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल पर लिमिटेड हाइट सब वे के निर्माण कार्य हेतु ट्राफिक ब्लॉक लिए जाने से 26 जून की अहमदाबाद से चलनेवाली अहमदाबाद-जम्मूतवी एक्सप्रेस अपने निर्धारित मार्ग भटिंडा, फिरोजपुर, जालंधर, पठानकोट के स्थान पर वाया भटिंडा, धुरी, लुधियान, जालंधर होकर चलेगी। वापसी में 2। जून की ट्रेन संख्या 19224 जम्मूतवी-अहमदाबाद एक्सप्रेस भी इसी परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएगी। इसी प्रकार 30 की अहमदाबाद से चलनेवाली अहमदाबाद-जम्मूतवी एक्सप्रेस भी अपने निर्धारित मार्ग फिरोजपुर, मखु, जालंधर के बजाए फिरोजपुर, लुधियाना, जालंधर होकर चलेगी और वापसी में 1 जुलाई की 19224 जम्मूतवी-अहमदाबाद एक्सप्रेस भी इसी परिवर्तित मार्ग से चलेगी।

देश के लिए समर्पित व्यक्ति व परिवारों की समर्पण की भावना सभी के लिए अनुकरणीय: मुख्यमंत्री

अजरपुरा गांव के मुख्य द्वार को लोकार्पण, आपातकाल के दौरान पीएम मोदी का था ठिकाना

आणंद (ईएमएस)। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने गुरुवार को आणंद के निकट ऐतिहासिक अजरपुरा गांव में समाज सेवी और संघ निष्ठ राष्ट्रवादी दाता परिवार द्वारा निर्मित भव्य, कलात्मक और प्रेरणादायी स्व. छोटालाल देसाई पटेल-कमलाबेन छोटाभाई पटेल ग्राम प्रवेशद्वार का लोकार्पण किया। उल्लेखनीय है कि अजरपुरा गांव में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व दूध उत्पादन के क्षेत्र में सहकारी प्रवृत्ति का जो विचार बीज रोपित हुआ था, वह आज अमूल के नाम से विश्वव्यापी बना है। इस गांव में स्व. प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री जी ने एक अदने किसान के घर में रात बिताई थी। वहीं, आपातकाल के दिनों में इस गांव के राष्ट्रवादी परिवारों के साथ वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भूमिगत रहे थे। विश्व प्रसिद्ध अमूल डेयरी में दूध का पहला संग्रह इस गांव ने किया था। मुख्यमंत्री ने इस गांव की राष्ट्रभक्ति और समर्पण की उज्जवल और प्रेरक विरासत को याद करते हुए हर्ष व्यक्त किया। भारतीय ऋषि-मुनियों की विचारधारा से प्रकट हुई योग परंपरा को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निष्ठावान प्रयासों से पूरे विश्व में मिली स्वीकृति पर खुशी व्यक्त करते हुए श्री रूपाणी ने कहा कि आज दुनिया के ज्यादातर देशों में योग साधना की जा रही है। योग से मन, बुद्धि और आत्मा पवित्र और निरामय बनती है। योग से राष्ट्र स्वस्थ और सशक्त बनता है। उन्होंने विश्वास जताया कि योग जगत को जोड़ने का और विश्व शांति का जरिया बनेगा। मुख्यमंत्री ने दाता परिवार के बुजुर्ग व सनातन धर्म के गादीपति तथा राष्ट्र और संघ के लिए जीवन समर्पित करने वाले स्व. अरविंदभाई पटेल बापू को आत्मीय भावांजलि दी। उन्होंने दाता परिवार की समाज निष्ठा और परोपकारी परंपराओं की सराहना करते हुए कहा कि देश के लिए समर्पण करने वाले और समाज के लिए जीने वाले व्यक्ति और परिवारों की समर्पण व सेवा की भावना समाज के लिए अनुकरणीय होती है। आणंद जिले को सरदार साहेब, भाईकाका और एच.एम. पटेल जैसी महान विभूतियों की कर्मभूमि बताते हुए उन्होंने कहा कि यह जिला समग्र राष्ट्र का पथप्रदर्शक और मार्गदर्शक रहा है। इस अवसर पर दाता परिवार के हर्षदभाई पटेल, जयेंद्रभाई पटेल और परिवारजनों ने मुख्यमंत्री कन्या केळवणी निधि में 51 हजार रुपए का योगदान दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री राहत निधि में योगदान के अलावा डिवाइन हेल्थ मिशन को वाहन (वैगन आर) का भी दान दिया। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर प्रवेशद्वार का लोकार्पण किया। दाता परिवार के विनोदभाई ने उपस्थित लोगों का शाब्दिक स्वागत किया।

प.रे. के अहमदाबाद मंडल पर योग दिवस मनाया गया

अहमदाबाद। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल पर विश्व योग दिवस पर मंडल स्तर पर योग शिबिर आयोजित की गई। मुख्य कार्यक्रम अहमदाबाद साबरमती स्थित सामुदायिक भवन पर आयोजित किया गया, जिसमें मंडल रेल प्रबंधक दिनेश कुमार की उपस्थिति में पतंजलि योगपीठ अहमदाबाद शाखा के वरिष्ठ योग प्रशिक्षकों द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को योग की शिक्षा एवं प्रेरणा दी।

संगीतमय अनुष्ठान आज

सूरत। 406 दीक्षा दानेश्वरी गुणरत्न सूरीश्वर के आचार्य पद प्राप्ति का 30 वर्ष पूर्ण होने के पावन अवसर पर पाल स्थित श्री ओंकार सूरी अराधना भवन में श्री वृहत्कल्प भाष्य आगम आधारित संगीत-गीत के अलावा भावनात्मक मंगलमय अनुष्ठान का आयोजन किया जाएगा। गुरु भक्त परिवार की ओर से यह कार्यक्रम 22 जून, शुक्रवार को सुबह 5ः30 बजे से होगा। इस अवसर पर आचार्य कुलचंद्र सूरीश्वर, आचार्य पुण्य रत्न सूरी, आचार्य यशोरत्न सूरी, आचार्य रविरत्न सूरी, आचार्य रश्मिरत्न सूरी, आचार्य संयम रत्न सूरी, आचार्य रश्मिराज सूरी, आचार्य मुनीश रत्नसूरी आदि श्रमण-श्रमणी वृंद पधारेंगे। इस मंगल प्रसंग पर महानुभावों का नवकारशी सम्मान किया जाएगा।

डीजल शेड वटवा में रेन वाटर हावौस्टिंग प्रणाली की स्थापना

अहमदाबाद। है पर बरसात के पानी को द्वारा 350 फीट गहरे शुद्ध अहमदाबाद मंडल के वटवा स्थित डीजल शेड में बरसात के पानी को संग्रहित कर पुनर्प्रयोग हेतु लाने के लिए रेन वाटर हावौस्टिंग प्रणाली की स्थापना की गई है। वटवा शेड के वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर आरएन भारद्वाज ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हरित पर्यावरण को बढ़ावा देने तथा व्यर्थ बहकर जानेवाली पानी को संग्रहित करने की इस पहल को अन्तगति लोकोशोड के प्रशासनिक भवन तथे हेवी किए हरिया भवन की छत जो कि लगभग 3665 एसक्यूएम संग्रहित करने के लिए यह प्लांट स्थापित किया गया है। इससे भूजल स्तर में बढ़ोत्तरी होगी, जिससे आसपास रहनेवाले निवासियों को भी इसका लाभ मिलेगा तथा उनका जलस्तर भी बढ़ेगा। जिससे इस वर्ष 20 लाख लीटर पानी संग्रहित किए जाने की योजना है। इसके तहत छत से आनेवाली पानी को सर्वप्रथम दस हजार लीटर की क्षमतावाली टंकी में संग्रहित किया जाएगा तथा ओवर फ्लो होकर व्यर्थ जानेवाली पानी को 14000 लीटर प्रति घंटे की दर से आठ ईंच व्यास के पाइप पानी के जल स्तरवाले बोर में डाल दिया जाएगा। इससे भूजल स्तर में बढ़ोत्तरी होगी, जिससे आसपास रहनेवाले निवासियों को भी इसका लाभ मिलेगा तथा उनका जलस्तर भी बढ़ेगा। भविष्य में 10 हजार लीटर की क्षमती की टंकी में संग्रहित बरसात के पानी को रेलवे इंजनों में भरने की योजना है, इसके लिए स्टोरेज पानी को डीएम प्लांट की स्टोरेज टैंक में भेजा जाएगा तथा वहां से शुद्ध पानी इंजनों में भरा जाएगा इससे पानी तैयार किए जाने पर होनेवाली राशि की बचत होगा।

10 जुलाई से डायमंड एक्सपोर्ट सूरत में

सूरत। डायमंड सिटी के नाम से दुनिया भर में चर्चित सूरत में, 10 से 12 जुलाई तक डायमंड एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। इस एक्सपो में थोक, फुटकर व्यापारियों, वितरकों, आयातकों और निर्यातकों को एक मंच पर लाने की कोशिश की जा रही हैं।

डायमंड एसोसिएशन के गौरव सेठी के अनुसार इस एक्स्पो में दुनिया भर के करीब 10000 लोग यहां पहुंचेंगे। इस एक्सपो में तुर्की, चीन, सिंगापुर, मलेशिया और पूर्वी अफ्रीका से बड़ी संख्या में लोग आएंगे। उन्होंने कहा यह देश की एक लूज डायमंड प्रदर्शनी हैं। इसमें लगभग 60 फ़ीसदी लोग पहली बार यहां अपने हीरों को प्रदर्शित करेंगे।

महादेव मीडिया
रोहताश यादव 9924144499, 7015339195
वीजिटिंग कार्ड, बिल बुक, लेटर पैड, बेनर, पोस्टर, आदि का डिजाइन बनवाने के लिए संपर्क करें। (हिन्दी, गुजराती)
हिन्दी, गुजराती न्युज पेपर डिजाईन करवाने के लिए संपर्क करें।
304 केवल कॉम्पलेक्ष नवा गाम, डिंडोली, उधना सूरत।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित, **संपादक :- सुरेश मौर्या** फोन नं. (9879141480) **RNI.No. : GUJHIN/2018/75100**, E-mail: krantisamay@gmail.com